

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :- रामावतार कुमावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 136/2016 किस्म प्रकरण :- 251-क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

1. श्रीमति मन्जूदेवी पत्नि श्री कृष्णलाल जाति जाट निवासी गांव बछरारा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज0) -प्रार्थी

बनाम

1. निशान्त सोनी पुत्र श्री रामकुमार सोनी जाति सोनी निवासी वार्ड संख्या 25/17 सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज0)

2. राजस्थान सरकार जरिये भू-प्रतिनिधि तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़

-अप्रार्थीगण

उपस्थित :-

1. श्री राकेश मनचन्दा अभिभाषक, प्रार्थी
2. श्री मागीरथ बिश्नोई अभिभाषक, अप्रार्थी नं. 1
3. पैरोकार राज

::- निर्णय -::

दिनांक :- 09.09.2019

यह प्रकरण माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर की अदालत के निर्णय दिनांक 17.12.2015 के द्वारा पत्रावली रिमाण्ड होकर आने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर दोनो पक्षों के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी गई।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी के नाम खरीदशुदा खातेदारी भूमि रोही टिलावाली तहसील सूरतगढ़ के खसरा नं. 6/6 में 6.325 है0 बरानी भूमि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज होकर कब्जा काश्त में चली आ रही है।

वकील प्रार्थी का कहना है कि प्राथी को अपने खेत तक जाने के लिए कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं है। इसिलये प्रार्थी अपने खेत तक जाने के लिए अप्रार्थी संख्या 1 के नाम रोही टिलावाली के खसरा नं. 6/8 की 2.373 है0 खातेदारी भूमि की पूर्वी दिशा में उत्तर से दक्षिण भाग में से होकर अपने खेत में आता है इसलिए अप्रार्थी नं. 1 के खातेदारी रकबा में से तीन

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

बिस्वा चौड़ा रास्ता स्वीकार किया जावे तथा प्रार्थी से डी.एल.सी. रेट से रकम जमा करवाई जावे या भूमि के बदले भूमि देने को तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

अप्रार्थी नं. 1 न्यायालय में उपस्थित आया व प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत करते हुए प्रार्थी द्वारा दर्ज तथ्यों को इन्कार करते हुए कहा कि प्रार्थी अपने खेत तक जाने के लिए पक्की सड़क से होकर एक पुराना कदीमी रास्ता प्रार्थी के खेत से चिता हुआ जाता है इसलिये नये रास्ते की आवश्यकता नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

दोनो पक्षों को सुनकर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 21.09.2015 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 21.09.2015 के विरुद्ध प्रार्थी द्वारा मा० राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर कैम्प सूरतगढ़ द्वारा इस अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.09.2015 को खारिज करते हुए अपने निर्णय दिनांक 17.12.2015 को पत्रावली रिमान्ड करते हुए निर्देश दिये की दोनों पक्षों को सुनकर पुनः निर्णय पारित किया जावें।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया व कहा कि प्रार्थी को अपने खातेदारी खेत ग्राम टीलावाली के खसरा संख्या 6/6 में 6.325 है० बारानी खातेदारी भूमि तक जाने के लिए कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं है। प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि में जाने लिये मंजूरशुदा रास्ता नहीं है। प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि के चिपते हुए दक्षिण दिशा में ग्राम टीलावाली की खसरा नं. 6/8 में स्थित अप्रार्थी सं. 1 की खातेदारी भूमि जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पुराना 63 नया के चिपते हुए स्थित है। अप्रार्थी सं. 1 के द्वारा प्रार्थी को मौका पर उसकी भूमि में चालू रास्ता में से गुजरने पर कई बार रोका जा चुका है। इसलिये प्रार्थी को अप्रार्थी नं. 1 के खातेदारी रकबा में से रास्ता स्वीकृत किया जावे व जितनी भूमि रास्तों में आती है उतनी भूमि की डी.एल.सी. रेट से रकम जमा करवाने के लिए तैयार है या भूमि के बदले भूमि प्रार्थी से अप्रार्थी को दिलवाई जावे। अप्रार्थी के विद्वान वकील ने अपनी प्रतिउत्तर बहस में कहा कि पिछले 50 वर्षों से पुराना आम रास्ता गांव टीलावाली से ढाढीयावाली व पदमपुरा गांव को जाने वाला रास्ता प्रार्थी के खेत से चिपता हुआ जाता है व यह रास्ता राष्ट्रीय राजमार्ग 15 हाल 63 से निकलकर दक्षिण पश्चिम में बहुत लम्बाई तक जाता है व प्रार्थी भी उसी रास्ते से आसानी से अपने खेत तक जाकर काशत करता है। यह रास्ता प्रार्थी के खेत से भी बहुत आगे के काशतकारों के खेतों तक जाता है। जिससे सारे काशतकार आसानी से



उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

इस रास्ते से अपने खेतों तक काश्त करने के लिये आते जाते हैं। अप्रार्थी का खेत पक्की सड़क से चिपता हुआ है। इसलिये प्रार्थी भी चौड़ा रास्ता स्वीकार करवाकर पक्की सड़क से सीधा जुड़कर अपने खेत की कीमत बढ़ाना चाहता है। रास्ता किसी काश्तकार को सुविधा या लाभ देने के लिये नहीं होता है, रास्ता खेत तक जाने के लिए आवश्यकता के लिए होता है। प्रार्थी को पहले से ही वर्षों से अपने खेत में काश्त करने के लिए जाने आने की सुविधा प्राप्त है। उसी चालू रास्ते को रिकार्ड में स्वीकार करवाने के लिए प्रार्थी कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है। अतः प्रा0पत्र खारिज किया जावे।

विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई एवं रिकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251-क में काश्तकार को रास्ते की सुविधा अत्यन्त आवश्यकता के रूप में ही उपलब्ध करवाई जाती है, अपने लाभ व सुविधा के लिये नहीं। प्रार्थी जिस पुरानी कदीमी रास्ते से अपने खेत तक आता जाता है उसी रास्ते को स्वीकार करवाने के लिए वह कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है सुविधा व लाभ के लिए अलग से नया रास्ता स्वीकृत करने का कानूनी प्रावधान नहीं है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 निरस्त किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 09.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



09/09/19

(रामावतार कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सहायक क्लर्क एवं
उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़

